

WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के उन्मुखे दौर के दौरान बातचीत शुरू हुई; औपचारिक रूप से 1994 में मारकेस, मोरक्को में इसकी पुष्टि की गई वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई

विशेषताएँ

- बाज़ार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- निर्यात सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

सब्सिडी बॉक्स

■ एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- » किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
- » उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविष्टियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- » एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
- » परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है
- » जो सदस्य इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
- » विकासशील देशों के लिये 10%
- » विकसित देशों के लिये 5%
- » भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

■ ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- » "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अभिकल्पित
- » ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
- » इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- » वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

■ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- » घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- » ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं
- » इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- » बिना किसी सीमा के अनुमत (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



दया याचिका

प्रलिमिस के लिये:

दया याचिका, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, कृपा करने की शक्तियाँ

मेन्स के लिये:

दया याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल के एक नरिणय में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने बलवंत सहि राजोआना की मौत की सज़ा को कम करने के लिये सरकार को नरिदेश देने से इनकार कर दिया है, इसके बजाय इसने सरकार को आवश्यकता पड़ने पर [दया याचिका](#) पर नरिणय लेने की अनुमति दी है।

- बलवंत सहि राजोआना को वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सहि की हत्या का दोषी ठहराया गया था।
- याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि चूँकि राज्य और भारत संघ 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित दया याचिका पर नरिणय नहीं ले पाए हैं, इसलिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिये।

न्यायालय का अवलोकन:

- न्यायालय ने गृह मंत्रालय के इस नषिकर्ष का हवाला दिया कि अब दया याचिका पर फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा।
- न्यायालय ने कहा है कि दया याचिका पर फैसला टालने के मंत्रालय के फैसले की "जाँच" करना न्यायालय के ऊपर नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर फैसला टालने का मंत्रालय का आह्वान वास्तव में याचिका को फलिहाल के लिये खारजि करने जैसा है।

दया याचिका:

परचिय:

- दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है, यह अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे मृत्युदंड या कारावास की सज़ा दी गई हो, द्वारा [राष्ट्रपति](#) या [राज्यपाल](#) से दया की मांग करते हुए किया जाता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के वचिर का पालन किया जाता है।
- सभी को जीने का मूल अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 21](#) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी वर्णित किया गया है।

संवैधानिक ढाँचा:

- भारत में संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, दया याचिका के लिये राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतमि संवैधानिक सहारा है। जब एक दोषी को कानून की अदालत द्वारा सज़ा सुनाई जाती है तो दोषी भारत के संविधान के [अनुच्छेद 72](#) के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है।
- इसी प्रकार भारत के संविधान के [अनुच्छेद 161](#) के तहत राज्यों के राज्यपालों को कृपा प्रदान करने की शक्ति दी गई है।

अनुच्छेद 72:

- राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कृपा करने, उसे रोकने, वरिम देने या कम करने या सज़ा को नलिंबित करने, परहिर करने की शक्ति होगी।

- उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो;
- उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का वसितार होता है;
- सभी मामलों में जहाँ मौत की सज़ा दी गई है।

अनुच्छेद 161:

- इसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के

लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, राहत देने, वरिम या छूट देने या नलिंबति करने, परहार करने या कम करने की शक्ति होगी जिससे राज्य की शक्ति का वसितार होता है।

- वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 साल की जेल की सज़ा काट चुका हो।

■ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से नपिटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में कानून की अदालत में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका रशितेदार राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टपिणियों और सफिरशियों के लिये भेज दिया जाता है।

■ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया का कार्य कैदी का अधिकार नहीं है। वह इसका दावा नहीं कर सकता।
- दया या क्षमादान उसके स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों के आधार पर दी जाती है क्योंकि वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं।

■ न्यायिक समीक्षा:

- एपु सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार (2006) एवं अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- न्यायालय ने कुछ आधार नरिधारित किये जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा है:

- यदि आदेश बेबुनियादी तरीके से पारित किया जाता है।
- यदि पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण है।
- यदि आदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों के प्रभाव में पारित किया गया है।
- अगर आदेश में मनमानी की भावना व्याप्त है।

दया याचिका से जुड़े कुछ अहम फैसले:

- 1981: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- 1994: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संवधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा।
- 1989: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूर्वक जाँच की थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72 की न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का नलिंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।

क्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ कीवर्ड:

- **क्षमा (Pardon)**: इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सज़ा को दंड, दंडादेशों एवं नरिरहताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
- **लघुकरण (Commutation)**: इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है, उदाहरण के लिये मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना।
- **परहार (Remission)**: इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है, उदाहरण के लिये दो वर्ष के कारावास को एक वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना।
- **वरिम (Respite)**: इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सज़ा के प्रावधान को कनिही विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिये महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सज़ा को परिवर्तित करना।
- **प्रवलिंबन (Reprieve)**: इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिये किसी सज़ा (विशेषकर मृत्युदंड) के निषिादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिये समय देना है।

अन्य देशों के प्रावधान:

■ संयुक्त राज्य अमेरिका:

- अमेरिका का संवधान महाभियोग के मामलों को छोड़कर राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये प्रवलिंबन अथवा क्षमादान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य कानून के उल्लंघन के मामलों में यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई

है।

■ यूनाइटेड कगिडम:

○ यूनाइटेड कगिडम में संवैधानिक राजा मंत्रिस्तरीय की सलाह द्वारा अपराधों हेतु क्षमा या दंडवशिम कर सकता है।

■ कनाडा:

○ आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पैरोल बोर्ड ऐसी राहत देने हेतु अधिकृत है।

नष्पिकरूषः

- दया याचिका एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करती है जो स्थिति और परस्थितियों के आधार पर वरदान या अभशिाप दोनों हो सकती है। दया याचिका को मंजूरी देने में अनावश्यक बाधाएँ एवं देरी से दोषियों तथा पीड़ितों दोनों को गंभीर असुवधि हो सकती है।
- यह अनजाने/अनायास न्याय में देरी कर सकता है जिससे पीड़ितों को कभी भी उचित एवं नष्पिकरूष न्याय नहीं मलि पाता है।
- यह पीड़ित के दर्द और पीड़ा को और बढ़ाएगा। भारतीय न्यायपालिका की उचित सुवधि एवं सुचारु कामकाज हेतु दया याचिका दायर करने तथा क्षमा देने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिये उचित सीमा अवधि व उचित नीतियों की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्नः

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी कसिी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपत को राष्ट्रपत शासन अधशेषित करने के लिये रपिर्त भोजना
2. मंत्रियों की नयिकृता करना
3. राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपत के वचिर के लिये आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधियी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधियिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2022)

स्रोतः द हद्वि

WTO को कृषिसिब्सडिी पर पुनः वचिर करने की आवश्यकता

प्रलिमिस के लयि:

WTO, GATT, सब्सडिी बॉक्स, पीस क्लॉज़, डी मनिमिस क्लॉज़

मेन्स के लयि:

WTO सुधार, सब्सडिी बॉक्स के मुद्दे, WTO सुधारों पर भारत के सुझाव

चर्चा में क्यों?

भारत के वित्त मंत्री ने [वशिव व्यापार संगठन \(WTO\)](#) से [कृषि सब्सिडी के मुद्दे](#) पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावित कर रही है।

- वित्त मंत्री ने [एशियाई विकास बैंक \(ADB\)](#) के गवर्नर्स द्वारा आयोजित संगोष्ठी 'एशिया को समर्थन देने वाली नीतियाँ' विषय पर यह बात कही।

नोट:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) के गवर्नर्स की संगोष्ठी एक **वार्षिक कार्यक्रम है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ADB के सदस्य देशों के सभी गवर्नर, प्रमुख नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ आदिको एक साथ लाती है।**
 - इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। ADB एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** ADB का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

WTO के तहत सब्सिडी

- **एम्बर बॉक्स:**
 - एम्बर बॉक्स सब्सिडी वह है जो अन्य देशों की तुलना में **किसी देश के उत्पादों को सस्ता बनाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकृत** कर सकती है।
 - उदाहरण: खाद, बीज, बजिली, सचिई और [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) जैसे इनपुट के लिये सब्सिडी।
 - वशिव व्यापार संगठन के अनुसार, कृषि के **एम्बर बॉक्स का उपयोग उन सभी घरेलू समर्थन उपायों के लिये किया जाता है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले माने जाते हैं।**
 - परणामस्वरूप व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स में आने वाले व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है।
 - सदस्य जो इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के अंदर अपना एम्बर बॉक्स समर्थन रखना चाहिये। (**डिमिनिमस क्लॉज़**)
 - विकासशील देशों के लिये 10%
 - विकसित देशों के लिये 5%
- **ब्लू बॉक्स:**
 - यह **"शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स"** है जो विकृत को कम करने के लिये डिज़ाइन की गई स्थितियाँ हैं।
 - कोई भी समर्थन जो आमतौर पर एम्बर बॉक्स में मौजूद होता है, उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है, यद्यपि इसके **लक्षिकियों को उत्पादन सीमा करने की आवश्यकता होती है।**
 - इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन सीमा निर्धारित कर अथवा किसानों को अपनी भूमिका एक हसिस् आरक्षित करने के लिये बाध्य कर उत्पादन को सीमा करना है।
 - वर्तमान में **ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है।**
- **ग्रीन बॉक्स:**
 - **घरेलू सहायता के** वे उपाय जो व्यापार को न के बराबर अथवा न्यूनतम रूप से बाधित करते हैं, उन्हें **ग्रीन बॉक्स कहा जाता है।**
 - ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के लिये सरकारी वित्त का उपयोग किया जाता है; **फसलों हेतु कोई मूल्य समर्थन नहीं होता है।**
 - इनमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।
 - इसलिये **"ग्रीन बॉक्स"** सब्सिडी की अनुमति बिना किसी सीमा के दी जाती है (कुछ परस्थितियों को छोड़कर)।

सब्सिडी मानदंडों पर फरि से विचार करने के प्रमुख कारण:

- **ग्लोबल साउथ के लिये असमान अवसर:**
 - वशिव व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से **कृषि वस्तुओं के निर्यात के संबंध में सामान्य तौर पर एक शिकायत रही है कि वैश्विक दक्षिण/ग्लोबल साउथ और उभरते बाज़ारों के दृष्टिकोण को व्यापार चर्चाओं में विकसित देशों के समान महत्त्व नहीं दिया गया है।**
 - 'ग्लोबल साउथ' व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को संदर्भित करता है।
- **खाद्य सब्सिडी सीमा के मुद्दे:** वशिव व्यापार संगठन के सदस्य देशों का खाद्य सब्सिडी बलि वर्ष 1986-88 के **संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये**, यह सीमा निर्धारण **अंतरराष्ट्रीय व्यापार वनियमों के तहत अपनाए गए संदर्भ मूल्य के लिये एक समस्या है।**
 - विकासशील देशों में कृषि और गरीब किसानों के लिये सब्सिडी की गणना नहीं की जाती थी तथा वशिव व्यापार संगठन द्वारा सब्सिडी पर रोक लगा दी जाती थी।

- व्यापार समझौतों की असंतुलित प्रकृति के कारण विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा दृढ़ है।
- बढ़ती खाद्य असुरक्षा: कोवडि-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य सुरक्षा के लिये उत्पन्न चुनौतियों की वजह से सब्सिडी मानदंडों पर फरि से विचार करना आवश्यक हो गया है क्योंकि खाद्य और उर्वरक सुरक्षा अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
- भारत की मांग: स्थायी समाधान के तहत भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के फार्मूले में संशोधन और वर्ष 2013 के बाद लागू कार्यक्रमों को 'पीस क्लॉज़' के दायरे में शामिल करने की मांग की है।

वश्व व्यापार संगठन का शांति समझौता:

- एक अंतरिम उपाय के रूप में वश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने दिसंबर 2013 में 'पीस क्लॉज़/शांति समझौता' नामक एक तंत्र पर सहमत जितार्ई और स्थायी समाधान के लिये बातचीत करने का संकल्प लिया।
- शांति उपबंध के तहत वश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने वश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान फोरम में विकासशील राष्ट्रों द्वारा नरिधारित सीमा में कसि भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमत वियक्त की।
- यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक क खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।

वश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO)

- परिचय:
 - वश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नरितरति एवं बढ़ावा देने का कार्य करता है।
 - इसे वर्ष 1995 में स्थापति कया गया था और वर्तमान में 164 देश (यूरोपीय संघ सहति) इसके सदस्य हैं।
 - यह सदस्य देशों को संवाद करने और व्यापार समझौतों को लागू करने, विवादों को सुलझाने एवं आर्थिक विकास तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
 - इसका मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- वश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति:
 - WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुलक एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर अपनाया गया।
 - WTO के नरिमाण की पृष्ठभूमि GATT के उरुग्वे दौर (वर्ष 1986-94) की वार्ता में तैयार हुई।
 - वश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, 1995 को परिचालन शुरू कया।
 - जसि समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे "मराकेश समझौते" के रूप में जाना जाता है। इस पर वर्ष 1994 में मोरक्को के मराकेश में हस्ताक्षर कयि गए।
- भारत वर्ष 1947 में GATT तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश बना।
 - GATT और WTO में मुख्य अंतर यह है क GATT जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को वनियमति करता था, वहीं WTO और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्क सेवाओं एवं अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे- व्यापार चहिन, डिज़ाइन व आवषिकारों से संबंधति व्यापार को भी शामिल कया जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधनियम, 1999 को कसिके दायतित्वों का पालन करने के लयि अधनियमति कया? (2018)

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- वश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लॉज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- खाद्य और कृषि संगठन
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रुपरेखा सम्मेलन
- वश्व व्यापार संगठन
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मलिते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-EU वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत ने वशिव व्यापार संगठन के व्यापार सुवधल समझौते (TFA) की पुष्टकी है ।
2. TFA 2013 के WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज का एक हसिसा है ।
3. TFA जनवरी 2016 में लागू हुआ ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

प्रश्न. व्यापार-संबंधति नविश उपाय (TRIMS) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

1. वदिशी नविशकों द्वारा आयात पर मात्त्रात्मक प्रतबिंध नषिदिध हैं ।
2. वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधति नविश उपायों पर लागू होते हैं ।
3. उन्हें वदिशी नविश के नयिमन से कोई सरोकार नहीं है ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

?????:

प्रश्न. वशिव व्यापार संगठन एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्टरीय संस्था है जहाँ लयि गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं । वशिव व्यापार संगठन का जनादेश क्या है और उसके नरिणय कतिने बाध्यकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वार्ता के नवीनतम दौर पर भारत के रुख का आलोचनात्मक वशिलेषण कीजयि । (2014)

प्रश्न. “वशिव व्यापार संगठन के अधकि व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्टरीय व्यापार का प्रबंधन एवं प्रोन्नतकिरना है । लेकिन वार्ताओं की दोहा परधिमृत्योनमुखी प्रतीत होती है, जसिका कारण वकिसति तथा वकिसशील देशों के बीच मतभेद है । भारतीय परपिरेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजयि । (2016)

प्रश्न. यदिव्यापार युद्ध' के वर्तमान परदृश्य में वशिव व्यापार संगठन को जदि बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं वशेष रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

[स्रोत: द हट्टि](#)

मुद्रा एवं वित्त पर रपिर् 2022-23

परलिमिस के लयि:

[आरबीआई की मुद्रा एवं वित्त पर रपिर्, शुद्ध शुन्य उत्सर्जन लक्ष्य](#)

मेन्स के लयि:

वृद्धि और वकिस, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य एवं वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

चर्चा में क्यौं?

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\) द्वारा मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रपिर्](#) 2022-23 में कयि गए एक अध्ययन के अनुसार, जलवायु परवित्तन हेतु भारत के अनुकूलन के लयि कुल संचयी व्यय वर्ष 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रपिर्:

परचय:

- यह **RBI** का वार्षिक प्रकाशन है।
- रपिर् में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के वभिन्न पहलुओं को शामिल कयि गया है।

थीम:

- मुद्रा और वित्त पर रपिर् 2022-23 का वषिय 'टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया' है।
- यह भारत के लयि जलवायु परवित्तन की चुनौतियों और अवसरों एवं कम कार्बन तथा जलवायु-लचीले वकिस पथ को प्राप्त करने में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है।

लक्ष्य:

- इसका उद्देश्य भारत में व्यापक आर्थिक और वित्तीय वकिस तथा उनके नीतगित प्रभावों पर वशिलेषणात्मक अंतरदृष्टि प्रदान करना है।

आकलन:

- रपिर् में भारत में टकिक उच्च वकिस के लयि भवषिय की चुनौतियों का आकलन करने हेतु जलवायु परवित्तन के चार प्रमुख आयाम- जलवायु परवित्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति, इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थरिता के नहितिार्थ एवं जलवायु जोखमिों को कम करने के लयि नीतगित वकिल्प शामिल हैं।

रपिर् की मुख्य वशेषताएँ:

अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत को वर्ष **2070 तक शुद्ध शुन्य उत्सर्जन** के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लयि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। रपिर् का सुझाव है कविवर्ष 2070-71 तक भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी 80 प्रतिशत तक होनी चाहिये।
- इसके लयि ऊर्जा उत्सर्जन में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के लगभग **5 प्रतिशत सालाना** की त्त्वरति कमी की आवश्यकता होगी।

हरति वित्तपोषण की आवश्यकता:

- जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले बुनयादी ढाँचे के अंतर को दूर करने के लयि भारत का **सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2030 तक** हरति वित्तपोषण आवश्यकता हेतु सालाना **कम-से-कम 2.5 प्रतिशत** होने का अनुमान है।
- वित्तीय प्रणाली को भारत के शुद्ध शुन्य लक्ष्य में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लयिर्याप्त संसाधन जुटाने और मौजूदा संसाधनों को पुनः आवंटित करने की आवश्यकता हो सकती है।

नीतगित हस्तक्षेप:

- इस रपिर् में सभी **नीतलीवर्स** (सार्वजनिक सेवाओं में परवित्तनों को नरिदेशति, प्रबंधति करने और आकार देने के लयि सरकार एवं उसके अभकिरणों द्वारा उपयोग में लाया जाना वाला उपकरण) में **प्रगत सुनश्चिति करने** के लयि एक संतुलति नीतगित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है जो **भारत को वर्ष 2030 तक अपने हरति संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध**

शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

■ जलवायु परिवर्तन के कारण वित्तीय जोखिम:

- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) नज्दी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

■ नीति उपकरण:

- केंद्रीय बैंकों के पास नविश के नरिण्यों को प्रभावित करने और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संसाधनों एवं ऋण के आवंटन के लिये कई नीतिगत साधन हैं।
- इसमें वभिन्न नयिमें के माध्यम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जलवायु एवं पर्यावरणीय जोखिमों पर वचिर करना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2021)

1. भारतीय रज़िरव बैंक (RBI) के गवरनर की नयिक्तकेंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
2. भारत के संवधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहति में RBI को नरिदेश जारी करने का अधिकार देते हैं।
3. RBI का गवरनर भारतीय रज़िरव बैंक अधनियम से अपनी शक्तिप्राप्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारतीय रज़िरव बैंक अधनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रज़िरव बैंक की स्थापना हुई थी।
- मूलतः रज़िरव बैंक नज्दी स्वामित्व में था, लेकिन वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकृत होने के बाद से यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
- RBI के मामले एक केंद्रीय नदिशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। बोर्ड की नयिक्तभारत सरकार द्वारा भारतीय रज़िरव बैंक अधनियम के अनुसार की जाती है।

स्रोत : द हद्रि

कृत्रमि बुद्धमिता का वनियमन

प्रलिमिंस के लयि:

कृत्रमि बुद्धमिता का वनियमन, [OpenAI का ChatGPT](#), ब्लैक बॉक्स, कृत्रमि बुद्धमिता अधनियम, [रसिपॉन्सबिल AI फॉर ऑल रपिरट](#)

मेन्स के लयि:

कृत्रमि बुद्धमिता का वनियमन और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संसद [कृत्रमि बुद्धमिता](#) अधनियम के एक नए मसौदे पर प्रारंभिक समझौते पर पहुँच गई है, जिसका उद्देश्य [OpenAI के ChatGPT](#) जैसी प्रणालियों को वनियमित करना है।

- वर्ष 2021 में AI में पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही तथा यूरोपीय संघ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मौलिक अधिकारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के जोखिमों को कम करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कानून का मसौदा तैयार किया गया था।

EU का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम:

■ परिचय:

- यह AI को सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित करता है जो सामग्री, पूर्व-सूचनाएँ, सफ़ारिशें या नरिण्यों जैसे आउटपुट उत्पन्न करता है।
- यह उच्चतम जोखिम वाली श्रेणी में **AI तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है**, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर रियल-टाइम फेशियल और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, नागरिकों का सामाजिक स्कोरिंग, व्यवहार को प्रभावित करने वाले तकनीक और कमज़ोर लोगों का शोषण करने वाली तकनीक शामिल है।

■ केंद्र बिंदु:

- यह AI सिस्टम पर केंद्रित है जिसमें **लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाने** की क्षमता है।
 - इनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोज़गार, कानून परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में AI शामिल हैं।
- इससे पहले कि उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम को बेचा जाए, **ये पारदर्शी, व्याख्या करने योग्य और मानव नरीक्षण की अनुमति देने के लिये सख्त परीक्षण से गुजरेंगे।**
- कम जोखिम वाले AI सिस्टम की **आवश्यकताएँ कम हैं** जैसे स्पैम फ़िल्टर या वीडियो गेम।

■ उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर वित्त तथा ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में **नैतिक प्रश्नों एवं कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान** करना है।
- कानून "प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित नुकसान को कम करने या रोकने और **AI की व्यापकता को बढ़ावा देने**" के बीच संतुलन बनाना चाहता है।
 - यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2018 ने वैश्विक डेटा संरक्षण शासन में इसे उद्योग के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। AI कानून का उद्देश्य "प्रयोगशाला से बाज़ार तक AI में उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में यूरोप की स्थिति को मज़बूत करना" और यह सुनिश्चित करना कि यूरोप में AI 27 देशों के ब्लॉक के मूल्यों और नयियों का सम्मान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को वनियमिति करने की आवश्यकता:

■ शामिल जोखिमों को लेकर अनश्चितता:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ रहा है और जैसे-जैसे तकनीक अधिक उन्नत होती जा रही है वैसे-वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कार चलाने, कैंसर का पता लगाने आदि जैसे विभिन्न कार्यों में सक्षम हो रही है, **जिसके कारण इससे जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं।**

■ ब्लैक बॉक्स:

- कुछ AI उपकरण इतने जटिल हैं कि वे "ब्लैक बॉक्स" की तरह हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि वे कैसे काम करते हैं और कुछ निश्चित उत्तरों या नरिणियों के साथ कैसे प्रस्तुत होते हैं।
- यह एक गुप्त बॉक्स की तरह है जो एक आउटपुट उत्पन्न करता है, लेकिन इसकी कार्यात्मक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

■ अशुद्ध और पूर्वाग्रही:

- AI उपकरण पहले से ही फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के कारण **गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी**, AI प्रणाली में नरिमति पूर्वाग्रहों के कारण अनुचित व्यवहार और हाल ही में GPT-3 एवं 4 जैसे बड़े भाषा मॉडल पर आधारित चैटबॉट के साथ **गलत कंटेंट का उत्पादन जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर चुके हैं।**
- ये चैटबॉट उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री/कंटेंट का उत्पादन करने में सक्षम हैं, इनमें और मानव द्वारा लिखित सामग्री में भिन्नता बता पाना मुश्किल है परंतु यह हमेशा सटीक अथवा कानूनी रूप से अनुमत नहीं हो सकता है।

■ भविष्य में इसके बर्ताव को लेकर संशय:

- AI कई अनूठी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रणालियों के विपरीत, डिज़ाइनर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि AI प्रणाली किस प्रकार व्यवहार करेगी। उदाहरण के लिये जब किसी कारखाने से एक पारंपरिक ऑटोमोबाइल को बाहर भेजा जाता है तो इंजीनियरों को पता होता है कि यह किस प्रकार काम करेगा। परंतु **सेल्फ-ड्राइविंग कारों के साथ इंजीनियर यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि नई स्थितियों में यह कैसे प्रदर्शन करेगी।**

वैश्विक स्तर पर AI का वनियमन:

■ भारत:

- **नीति आयोग** ने AI के लिये राष्ट्रीय रणनीति और **रसिपॉन्सबिल AI फॉर ऑल** रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज़ जारी किये हैं।
- भारत सामाजिक और आर्थिक समावेशन, नवाचार और भरोसे को प्रोत्साहित करता है।

■ ब्रिटन:

- ब्रिटन ने AI के लिये मौजूदा नियमों को लागू करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में नियमों से जानकारी एकत्रित करने के लिये सरल दृष्टिकोण को अपनाया है।
- कंपनियों द्वारा पालन किये जाने वाले पाँच सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया गया जिसमें सुरक्षा और मज़बूती; पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता; निष्पक्षता; जवाबदेही तथा शासन; प्रतिसिपर्द्धात्मकता एवं निवारण की व्याख्या की गई है।

■ संयुक्त राज्य अमेरिका:

- अमेरिका ने **AI बलि ऑफ राइट्स (AIBoR)** हेतु एक बलूपरि जारी किया, जिसमें आर्थिक एवं नागरिक अधिकारों के लिये AI के नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया गया है तथा **इन प्रभावों को कम करने हेतु पाँच सिद्धांत दिये गए हैं।**
- यह बलूपरि स्वास्थ, श्रम और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों हेतु नीतिगत हस्तक्षेप के साथ यूरोपीय संघ की तरह **क़ैतजि रणनीति के बजाय AI शासन के लिये क्षेत्रीय विशेष दृष्टिकोण का समर्थन करता है**, जिससे क्षेत्रीय संघीय एजेंसियों को अपनी योजनाओं को तैयार करने की अनुमति मिलती है।

■ चीन:

- वर्ष 2022 में चीन ने वशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और AI को लक्षित करने वाले दुनिया के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं।
- **इसने अनुशंसा एल्गोरिदम को वनियमिति करने हेतु कानून बनाया**, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि सूचना का प्रसार कैसे करते हैं।

आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वनियमिति करने में एक सरल नियामक ढाँचे का निर्माण शामिल है जो AI की क्षमताओं को परिभाषित करता है एवं **दुरुपयोग हेतु अतिसंवेदनशील लोगों की पहचान करता है।**
- व्यवसायों की डेटा तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए सरकार को डेटा गोपनीयता, अखंडता और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **ब्लैक-बॉक्स के दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिये** एक अनिवार्य स्पष्टीकरण लागू किया जाना चाहिये, जो व्यवसाय हेतु लिये गए प्रत्येक निर्णय के पीछे के तर्क को समझने में मदद करेगा।
- इसके प्रभावी नियमों को तैयार करने के लिये नीति निर्माताओं को वनियमन के दायरे और इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिये, उन्हें उद्योग के विशेषज्ञों एवं व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट लेना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न 1. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), नमिनलखिति में से कसि कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में वदियुत की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
3. रोगों का नदिन
4. टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन
5. वदियुत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचिर कीजिये: (2018)

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोतः द हृदि

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप

परलिमिंस के लयि:

डेबट-फॉर-क्लाइमेट सवैप, पेरसि समझौता, विकासशील छोटे द्वीपीय राज्य

मेन्स के लयि:

जलवायु वृत्ति का महत्त्व, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिये डेबट-फॉर-क्लाइमेट सर्वेय का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है, लेकिन यह कुछ देशों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। दुरभाग्य से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देश अक्सर अपने लचीलेपन को दृढ़ करने के लिये आवश्यक नविश को वहन करने में सबसे कम सक्षम होते हैं।

- यह इन देशों को लंबे समय तक वित्तीय संकट का सामना करने के खतरे में डालता है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहायता पर विश्वास करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
- डेबट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप एक नवाचारी वित्तीय लखित है जिसका उद्देश्य जलवायु नविश के लिये राजकोषीय वसितार के साथ इस मुद्दे को संबोधित करना है।

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप:

- **परिचय:**
 - डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप ऋणी देशों को अपने ऋण बोझ को कम करते हुए जलवायु पर सार्वजनिक कार्रवाई करने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।
 - इन स्वैपों में **नीतिगत प्रतबिद्धताओं या करज़दार देशों द्वारा किये गए व्यय के बदले ऋण को कम करना** शामिल है।
 - आधिकारिक **द्विपक्षीय देश और वाणिज्यिक ऋण** दोनों डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप में शामिल हो सकते हैं।
 - द्विपक्षीय डेब्ट स्वैप में जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये **आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों को पहले से प्रतबिद्ध ऋण सेवा भुगतानों को पुनर्निर्देशित** करना शामिल है।
 - पछिले एक दशक में नमिन और मध्यम आय वाले देशों के बीच डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वैप अपेक्षाकृत लोकप्रिय हुआ है।
 - **बहुपक्षीय विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** जैसे बहुपक्षीय संगठन ऋण-राहत उपाय के रूप में इस साधन की वकालत करते रहे हैं।

- इतिहासः

- डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप नेचर-फॉर-डेब्ट स्वेप का एक रूप है, जिस पहली बार वर्ष 1980 के दशक में जैवविविधता के संरक्षण और ऋण राहत के बदले में उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- पहली नेचर-फॉर-डेब्ट स्वेप वर्ष 1987 में बोलिविया और एक गैर-सरकारी संगठन कंज़र्वेशन इंटरनेशनल के बीच की गई थी।
- 2000 के दशक में डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप एक व्यापक अवधारणा के रूप में उभरा, जिसमें न केवल प्रकृतिसंरक्षण बल्कि जलवायु शमन और अनुकूलन भी शामिल हैं।
- जलवायु के बदले पहला ऋण वर्ष 2006 में जर्मनी और इंडोनेशिया के बीच लागू किया गया था, बाद में ऋण राहत के बदले में इसे वनों की कटाई और वन क्षरण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने (Reduce Greenhouse gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)) हेतु प्रतबद्ध किया गया था।

■ लाभ:

- लेनदारों हेतु:
 - जलवायु के बदले ऋण का आदान-प्रदान उनके विकास सहयोग और जलवायु वित्त उद्देश्यों को बढ़ा सकता है, उनकी ऋण वसूली की संभावनाओं में सुधार कर सकता है एवं ऋणी देशों के साथ उनके राजनयिक संबंधों को मजबूत कर सकता है।
- देनदारों हेतु:
 - जलवायु हेतु ऋण का आदान-प्रदान उनके बाहरी ऋण स्टॉक और सेवा को कम कर सकता है, अन्य विकास आवश्यकताओं हेतु वित्तीय संसाधनों को मुक्त कर सकता है, जलवायु कार्रवाई में उनके घरेलू नविश को बढ़ा सकता है, साथ ही उनके पर्यावरण तथा सामाजिक परिणामों में सुधार कर सकता है।
- दोनों पक्षों हेतु:
 - जलवायु के बदले ऋण का आदान-प्रदान आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जो समाधान के साथ-साथ पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान कर सकता है।

■ चुनौतियाँ:

- लेनदार देश मुख्यतः जलवायु के लिये ऋण का आदान-प्रदान करने से हचिकचाते हैं जब तक कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये तैयार नहीं किया जाता है कि जलवायु कार्रवाई के प्रति सार्वजनिक व्यय प्रतबद्धता शेष ऋण सेवा के मूल्य से बेहतर है।
- हालाँकि सशर्त जलवायु अनुदानों को तैयार और संरचित किया जाता है ताकि उन्हें डायवर्ट करना असंभव हो जो केवल जलवायु नविश के उद्देश्य हेतु लक्ष्य हैं।

ऋणदाता देशों की डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप में संलग्नता:

- लेनदार देशों को जलवायु हेतु डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप में संलग्न होना चाहिये क्योंकि पेरिस समझौते और ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो (GFANZ), वित्तीय संस्थानों के एक वैश्विक गठबंधन के हस्ताक्षरकर्त्ताओं की प्रतबद्धता स्वच्छ, जलवायु-लचीला भवषिय बनाने के लिये विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप अपनी प्रतबद्धताओं को पूरा करने का एक तरीका है।

डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप छोटे द्वीपीय देशों हेतु सहायक:

- छोटे द्वीप विकासशील राज्य (SIDS) दो चुनौतियों का सामना करने हेतु डेब्ट-फॉर-क्लाइमेट स्वेप पर नज़र रख रहे हैं **बढ़ते जलवायु जोखिम के अनुकूल होना एवं वित्तीय संकट से उबरना।**
- जलवायु के लिये ऋण के आदान-प्रदान में भाग लेकर SIDS अपने बाहरी कर्ज़ को कम कर सकता है और जलवायु कार्रवाई सहित अन्य विकासात्मक ज़रूरतों के लिये वित्तीय संसाधनों को मुक्त कर सकता है। इससे उन्हें जलवायु कार्रवाई में अपने घरेलू नविश को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

